They never care for Ayurveda system. If such system is allowed to continue, then Ayurveda system books will not be understood at all after 10 years.

The courses adopted by all these universities never prescribe any text-books; they have prescribed only some syllabi and the Professors prepare notes and teach the students. The products are neither well up in Ayurveda nor in allopathy. In Shri Morarji Desai's language, they are neither fish nor fowl. Shri Sampurnanand has also bitterly criticised this sort of courses and has clearly stated that they are white elephants. Even now what are they doing? They are registering their names as Ayurvedic practitioners, but they never touch even a single medicine of Ayurveda; they always deal with allopathic medicines. It was felt by the Health Ministry that they should eradicate Ayurveda from this country through Ayurvedists and that is why such a course was prescribed and it is still going on. Those who deal with Ayurveda do not know the 'ABC' of Ayurveda. There must be one controlling office, so that Ayurvedic education and treatment are standardised. That is why I have brought forward this Bill.

In this Bill I have tried my best to have representatives from all sorts of organisations. Even these products of integrated course have been absorbed in this Bill. According to the Bill, there will be a Council consisting of all sorts of representatives from the various States, and that Council will be established on the model of the Indian Medical Council, and that Council will control the education and treatment *in toto*. Therefore, I will request the hon. House to accept my proposal and send this Bill for eliciting public opinion.

In this connection, I want to state one more thing. The thing is this. In 1835, Lord Macaulay abolished the Ayurvedic system in this country. Since then, not even a single pie was given to the Ayurvedic system of medicine, and all the allotments were confined only to the allopathic treatment. Even today the position is that only 20 percent of the population is being benefited by the allopathic treatment. For the benefit of only 20 per cent of the population, Government is spending crores of rupees without caring for the 80 per cent of the population which entirely depend on the indigenous system of medicine. At present the Government is allowing only 4 or 5 per cent of the allotment under Health for the improvement of the indigenous system of medicine and for this purpose they have included, in the name of indigenous system of medicine, homoeopathy, unani, Ayurveda, hydropathy, naturopathy and all other siddhas... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may please ..

SHRI A. T. SARMA : I will finish in three minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he wants, he can have more time. We have to take up the half-an-hour discussion now. The hon. Member may continue his speech on the next occasion.

18.30 hrs.

SUSPENSION OF PRODUCTION OF FILMS IN BOMBAY*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we shall take up the half-an-hour discussion. Shri George Fernandes.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सिनेमा का धन्धा हिन्दुस्तान के बहुत ही बड़े उद्योगों में से एक है। इस में करीब 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इस धन्धे से हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का टर्न-ओवर, निर्माण होता है। सरकार को हर साल 70, 80 करोड़ रुपया इस धन्धे से मिलता है, 40 करोड़ रुपया एन्टरटेनमेंट टैक्स के रूप में और 30, 40 करोड़ रुपया एक्साइज, इनकम टैक्स आदि दूसरे करों या इस धन्धे से सम्बन्धित दूसरे उद्योगों के जरिये।

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़]

मगर इस धन्धे का महत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस में कितनी पूंजी लगी हुई है और सरकार को इस से कितना पैसा मिलता है। मेरे ख्याल में सिनेमा आज हिन्दुस्तान के लोगों, और खास कर नौजवानों, के मन पर बहुत ही ज़बर्दस्त असर डालने वाला माध्यम बन गया है। समाज को बनाने की, अथवा बिगाड़ने की, सिनेमा जो ताकत रखता है, वैसी ताकत आज बहुत ही कम दूसरी संस्थाओं के पास है।

लेकिन पिछले एक दो महीनों में इस धन्धे में जो झंझट चले हैं, उन से यह बात साबित हो चुकी है कि इस धन्धे के हर एक स्तर पर, चाहे सिनेमा बनाने वाले लोग हों, उसका वितरण करने वाले हों, उसको दिखाने वाले अर्थात एक्सहिबिटर्ज़ हों या उस में काम करने वाले लोग हों, उन सब में काफी गन्दगी है, जिस को साफ़ करना बहुत ही आवश्यक है। जब दो महीने पहले यह झगड़ा चला, तो हमारे जैसे लोगों ने यह उम्मीद की थी कि सरकार ऐसा कदम उठायेगी, जिस से इस धन्धे में पाई जाने वाली गलतियों और ख़राबियों को हमेशा के लिए दूर करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन अनुभव कुछ और ही रहा। मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप तो ज़रूर किया, लेकिन पहली बार उन के हस्तक्षेप को उन्हीं लोगों ने ठुकराया, जो यहां से मान कर गये थे। कुछ मरहम-पट्टी तो लगाई गई है, लेकिन में समझता हूं कि बुनियादी दिक्कतों और खराबियों को दूर करने की दृष्टि से मन्त्री महोदय ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

इस धन्धे में और इन झगड़ों में—पांच, छः अलग-अलग गुट हैं। एक तो सिनेमा बनाने वाले हैं। दूसरे कलाकार हैं, या जो कलाकार कहलाते हैं—उन में से काफ़ी कलाकार नहीं हैं। तीसरे वितरण करने वाले डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ हैं। चौथे सिनेमा दिखाने वाले, सिनेमा थियेटर चलाने वाले एक्सहिबिटर्ज़ हैं। और पांचवे वे हैं, जिन के बारे में बहुत कम कहा जाता है, लेकिन जिनके बारे में सब से ज्यादा कहना चाहिये वे हैं पांच लाख से अधिक कर्मचारी, जो इस धन्धे में हर एक स्तर पर, स्टुडियो, दफ्तर और सिनेमा हाउसिज़ में काम करते हैं।

एक बार- जब इस प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो मैंने उन्हीं लोगों की बात उठाई थी। मैंने कहा था कि सिनेमा वालों ने कुछ साल पहले एक फिलम बनाई थी, "हम सब चोर हैं" कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर इस धन्धे में सब चोर ही भरे हुए हैं। मेरी राय में अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले दो महीनों में इन लोगों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला है। अगर उन्हीं लोगों के बयानों को देखा जाये तो मैंने जो कुछ कहा था, उस का समर्थन उन्हीं के द्वारा हो जाता है।

सब से पहले प्रोडयूसरों ने झगड़ा शुरू किया, जिसके कारण यह मामला हमारे सामने आया। प्रोड्यूसर्ज़ ने कहा कि लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने जो सिनेमा बनाये, वे चल नहीं पाये, जिससे कई प्रोड्यूसर्ज़ का दिवाला निकल गया; ऐसे लोगों की मुसीबत में मदद करने के लिये कोई डिस्ट्रिब्यूटर खड़ा नहीं हुआ; ये डिस्ट्रिब्यूटर और एक्सहिबिटर हम पर जुल्म करते हैं। ये प्रोड्यूसर्ज़ के आरोप थे।

उनके साथ कलाकार कहलाने वाले काफ़ी लोग भी जम गये, क्योंकि उनमें कई लोग ऐसे हैं, जो कलाकार भी हैं और पैसा बनाने के बाद प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक्सहिबिटर्ज़ पर आरोप लगाये। इसी तरह एक तरफ डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ ने प्रोड्यूसर्ज़ और एक्सहिबिटर्ज़ पर और दूसरी तरफ़ एक्सहिबिटर्ज़ ने प्रोड्यूसर्ज़ और डिस्ट्रिब्यूर्ज़ पर आरोप लगाना शुरू किया। मैं इन सब की बयानबाज़ी में से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

डिस्ट्रिब्यूटर्ज की तरफ़ से एक पर्चा निकाला गया, जिस में लाल स्याही में कहा गया है :

"EXHIBITION : RATIONALISE OR NATIONALISE"

उस के बाद उस पर्चे में यह शीर्षक दिया गया है :

"RAMPANT BLACK MARKETE IN THE FILM INDUSTRY"

इस धन्धे के लोग खुद कहते हैं :

"The Producers of today are mere agents of these stars to collect huge amounts for these stars and Music Directors and for themselves.

"The Producers are fully secured in their nefarious games by realising minimum guarantees from their Distributors.

"This corruption reached its peak in the year 1967. The volcano has now erupted. Distributors have revolted to be made victims any more...

"We demand nationalisation which will be highly advantageous to the Government from Revenue side.

'Two lists are enclosed which will give you a true picture of the high amonnts charged by stars etc. on the production side on high theatre rentals charged by Exhibitors"

डिस्ट्रिब्यूटर्ज वितरकों की ओर से ये आरोप लगाये गये हैं एक तरफ़ तो प्रोड्यूसर्ज पर, दूसरी तरफ़ कलाकारों पर और तीसरी तरफ़ सिनेमा चलाने वाले लोगों पर। उन की मांग है कि सिनेमा थियेटर्ज का तत्काल राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

एक्सहिबिटर्ज ने भी एक पर्चा निकाला है, जो कि मंत्री महोदय को पहुँचाया गया है। उन के कानवीनर, श्री राजेश्वर दयाल, का आरोप है कि हम लोग, एक्सहिबिटर्ज, तो बिल्कुल ठीक हैं; हमारा धन्धा बहुत बिगड़ा है, लेकिन उस को बिगाड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, बल्कि डिस्ट्रिब्यूटर्ज और प्रोड्यूसर्ज हैं।

वे कहते हैं :

"The cost of production and the price charged from the Distributors are being increased by the Producers from year to year without any rational or economic criteria and the Distributors have also been acting as their accomplices in this respect. The only reason for this is that, as a general rule, neither the producer nor the Distributors have any stake or investment of their own".

आगे वे कहते हैं :

"It is a fact that during the last 7 to 10 years four male artists, four female artists and four music directors, along with their producer friends, have not only made fabulous profits totalling many crores of rupees (a major portion of that out of books) but also controlled the producers bodies like the IMPPA and the Film Guild"...

आगे चल कर वे कहते हैं :

"The facts enumerated above prove beyond any doubt that the exhibitors are made a scapegoat by the unholy trinity of the Producers, the stars and the Distributors for their own sins and wrongs in order to confuse both the authorities and the public".

एक्सहिबिटर्ज ने एक मेमोरेंडम में कुछ आंकड़े भी दिये हैं। वे कहते हैं :

"It is a well known fact that during the last 7 to 10 years the prices charged by the Producers have gone up by 500 to 600 per cent. The following table succinctly depicts this phenomenon :

"Pictures starring Raj Kapoor,

"Devanand or Rajinder Kumar :

1960 में ऐवेरेज मिनिमम गारंटी थी डेढ़ से दो लाख और 1967 में दस से बारह लाख।

"Pictures showing Dilip Kumar :

1960 में ऐवेरेज मिनिमम गारंटी थी दो से ढाई लाख और 1967 में पंद्रह लाख या उस से ज्यादा।

इस से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि असल में इस धन्धे की बीमारी काले पैसे की बीमारी बन गई है। इस धन्धे से सम्बन्धित

[श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़]

हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से पैसा बनाने और काले पैसे के रूप में कमाने, के काम में फंसा हुआ है। इस लिये हम चाहेंगे कि एक तो इस धन्धे का महत्व समझ कर और दूसरे इस में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के हित का ख्याल रख कर, जिन की ज़िन्दगी इन बड़े लोगों के आपसी झगड़ों के कारण बर्बाद हो रही है, सरकार इस धन्धे के बारे में अपने रुख़ को स्पष्ट करे और कुछ ठोस फ़ैसले करे।

मैंने सुना है कि चन्द दिन पहले फिल्म फिनांस कार्पोरेशन के चेयरमैन, श्री हिम्मत सिंह की ओर से सरकार को एक नोट पेश किया गया था। मैं आप की इजाजत से उस नोट* को सदन-पटल पर रखना चाहूँगा। मुझे अफसोस है कि इस धन्धे से सम्बन्ध रखने वाले और इस बारे में काफ़ी तजुर्बा रखने वाले व्यक्ति ने यह जो नोट बना कर भेजा हैं, उस पर मंत्री महोदय ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। श्री हिम्मत सिंह ने इस धन्धे की बुराइयों और इस में होने वाले पैसे के गोल-माल के बारे में तो कहा ही है, लेकिन उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सिनेमागृह, सिनेमा थियेटर, का क्या रेट होना चाहिए, इसके बारे में सरकार को कुछ ठोस नियम बनाने चाहिए।

बहुत से सिनेमा थियेटर ऐसे हैं जो सिर्फ विदेशी फिल्में चलाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ हिन्दी फिल्में चलाते हैं। यह तरीका बदलना चाहिये। सब सिनेमा घर हर तरह की फिल्म चलाने का काम करें—यह उन का दूसरा सुझाव है।

18.40 hrs.

[Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

तीसरा सुझाव उन्होंने यह दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का धन्धा है, इसे सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। उन का यह कहना है कि अगर सरकार इस धन्धे को अपने हाथ में ले ले, तो इस में कोई नुकसान होने की बात नहीं होगी। आज बहुत से प्रोडयूसर फिल्म कारपोरेशन से मदद ले कर फिल्में बनाते हैं, अगर सरकार इन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का काम अपने हाथ में लेले और किसी कारपोरेशन के ज़रिये करे, तो फिर मिनीमम गारन्टी की जो बात है, जिसके कारण कि आज काले पैसे की शुरूआत होती है, वह खत्म हो जायगी। आज एक्ज़ीबिटर्स के लेवल पर जो ज्यादा पैसा दे कर फिल्म चलाई जाती है और उससे काला धन्धा पनपता है, वह नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस के बारे में अपनी स्पष्ट राय सदन के सामने रखें।

हम बहुत अर्से से कहते आये हैं कि एक्ज़ीबिशन का काम, सिनेमा थियेटर चलाने के काम का राष्ट्रीकरण हो। हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि इस काम को म्युनिस्पिलटी के हाथ में दे दो, राज्य सरकारों के हाथ में दे दो और कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जिससे एक्ज़ीबिशन के काम की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की हो। यदि आप ध्यान से देखें तो काले पैसे की शुरूआत यहीं से होती है, क्योंकि इस के लिये पैसा तो पब्लिक से ही वसूल करना होगा, यदि आप इस धन्धे को अपने हाथ में ले लें तो इस बिमारी को दूर करने में काफ़ी कामयाबी मिल सकेगी। मैं तो यह चाहूँगा कि सरकार इस पर भी अपनी कोई ठोस राय पेश करे।

अब एक आखरी जुमला कह कर मैं खत्म करने वाला हूँ। सिनेमा कर्मचारियों की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहता हूं—कुछ साल पहले बम्बई में इन कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में एक बी० जी० खेर कमेटी बनी थी, इस कमेटी की ओर से सिनेमा कर्मचारियों के वेतन, उन के काम की सभी चीजों के बारे में कुछ सिफारिशें आई थीं,

*The Speaker subsequently not having accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। के० अब्बास जैसे आदमी ने, जिनका सिनेमा के धन्धे से बहुत से पहले से सम्बन्ध है, "मैनस्ट्रीम" के ता० 27 के अंक में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इस धन्धे में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत पर रोशनी डाली है। वह लिखते हैं कि एस्सिटेंट कैमरा मैना, जिस की एक मामूली गलती से लाखों रुपये का नुकसान प्रोडयूसर का हो सकता है, उसको आज 100 रु० से भी कम तनख्वाह मिलती है। जो लाइट का इन्तजाम करने वाले कुली होते है, जिनके फोकसिंग करने में, लाइट बनाने में अगर मामूली सी भी गलती हो जाये तो जो सिनेमा में काम करने वाली खूबसूरत लड़की है वह खूबसूरत नहीं रहेगी, बदसूरत दिखाई देगी, उस कुली की तनख्वाह महीने की 50 रु० है। यह हालत इस धन्धे में काम करने वाले कर्मचारियों की हैं। इस बात का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मजदूर यूनियन नहीं कर रही है, बल्कि इस धन्धे में काम करने वाला एक प्रोडयूसर डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब कर रहे हैं। मैं मंत्री साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे इन कर्मचारियों की हालत को सुधाररने का काम करें। एक तरफ दलीप कुमार 18 लाख रुपये लेता है, वहीदा रेहमान 8 लाख रुपये लेती है नूतन 8 लाख रुपये लेती है, राजेन्द्र कुमार 15 लाख रुपये लेता है, राजकपूर 15 लाख रुपये लेता है, दूसरी तरफ ये कर्मचारी जो इन लोगों की तस्वीरों को जनता तक पहुँचाने वाले हैं, कैमरा मैन, अस्सिटेंट कैमरा मैन, कुली 50 रु० या 100 रुपये तनख्वाह में वहां पर मर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है जो खुद को कलाकार कह कर गरीबों की जिन्दगी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करते हैं, खुद का जीवन ऐसा बतलायेंगे जिस का दुनिया पर असर पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को इतनी बुरी हालत में वहां पर डाल रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़ दिया है, अपनी ही बनाई हुई कमेटी की शिफारिशों को अमल में लाने का काम आज तक नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि इस पर तात्कालिक निर्णय किया जाये।

एक आखरी बात – सभापति महोदय— सिनेमा के धन्धे से सम्बन्ध रखने वाले या इस धन्धे में काम करने वाले कुछ लोगों ने मिल कर "दि न्यू सिनेमा मूवमेन्ट" नाम से एक नया प्रयोग शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री साहब ऐसे लोगों से मिलें को कुछ आदर्श रख कर, सिर्फ पैसे के पीछे न रह कर, काले पैसे का काम न कर के, अच्छा काम करना चाहते हैं। इन लोगों ने जो न्यू सिनेमा मूवमेन्ट का आन्दोलन शुरू किया है आप इसको आन्दोलन कहिये या सिनेमा बनाने का उद्योग कहिये मन्त्री साहब इनको प्रोत्साहित करें, कुछ पैसे इनकी मदद करें, आर्थिक मदद करें, ताकि यह धन्धा जो बिगड़ा हुआ है, वे इस को सुधारने का काम कर सकें।

SHRI BABURAO PATEL (Shajapur): Sir, we had a lot of sound any fury from the hon. Member, Mr. Fernandes. He did not tell anything new to the Minister, who is conversant with almost all the aspects and difficulties of the film industry. In fact, had he not been seduced to become a Minister, it was quite possible Mr. Shah would have become a bankrupt producer. He is so fond of art.

MR. CHAIRMAN: He can only put a question.

SHRI BABURAO PATEL: I am associated with the film industry for more than 44 years. If I do not speak, nobody speaks for the industry.

MR. CHAIRMAN: That is a different matter. I too have been in this presiding business for quite a long period.

SHRI BABURAO PATEL: Mr. Fernandes mentioned three different professions—producer, distributor and exhibitor. 82 per cent of the producers have become bankrupt. Nearly 50 per cent

[Shri Baburao Patel]

of the distributors have become bankrupt. But so far not a single exhibitor has become bankrupt. The exhibition end is the money-receiving end and that has to be controlled one way or other.

It is not possible under the present Constitution to control production. That will interfere with the freedom of expression of a citizen. But the Minister can certainly look after the exhibition side, because there are a lot of malpractices of which the Minister is aware. These can be controlled on the ground of monopoly which is being enjoyed by the exhibitors. They virtually blackmail the producers.

MR. CHAIRMAN : I do not want to interrupt an interesting speech. But under the rules, the names are balloted only for putting a question.

SHRI BABURAO PATEL : Then, I will put a question, Sir. Will the minister think of the possibility of including the exhibition trade under the Monopolies Act ?

SHRI ANANTRAO PATIL (Ahmednagar) : What is the long-term solution for the crisis in the film industry ? How to do away with the black money ? Can the Finance Ministry find some way to collect this black money and make arrangements for repayment of this amount to the artistes in their old age ? Producers, distributors and exhibitors have become a vicious circle, each one trying to extract money from the other. How can it be broken ? The State Government are getting crores of rupees by way of entertainment tax. Why should they not build more cinema houses and get more entertainment tax ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, अभी जो संकट फिल्म उद्योग में पैदा हुआ वह टलता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसका कोई पक्का इलाज नहीं हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि फिल्मों के निर्माता, उसमें धन लगाने वाले, वितरण करने वाले और जनता तक उनको पहुँचाने वाले, इन सब के स्वार्थों में और हितों में इस तरह से ताल-मेल बिठाई जाये कि फिल्म एक कला के रूप में विकसित हो सके और देश में जागृति पैदा करने का काम कर सके ? क्या मन्त्री महोदय इस सुझाव से सहमत हैं कि अगर आज सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि जिससे सिनेमा घरों के मालिक अनाप-शनाप किराया लेकर इस उद्योग को बिगाड़ न सकें ? क्या सरकार ने इस दिशा में विचार किया है ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : Sir, immediately after the Minister's statement that he had settled the dispute between the distributors on the one hand and the producers on the other there was a strike which continued for some days. May I know why this strike at all was allowed to take place and did the Minister take any steps to prevent it ? May I also know what is the long-term solution to the disputes that are constantly going on between three or four parties in the whole drame ?

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister-

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : मुझे भी मौका दीजिये ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member did not send his name even.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : तो फिर क्या, हम सिर्फ कोरम ही बनाकर बैठे रहें ? फिर तो मैं कह दूंगा कि हाउस में कोरम नहीं है । अगर यही बात है कि हम कुछ पूछना चाहें और आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर मैं कहूँगा कि कोरम नहीं है । यह बिल्कुल गलत बात है कि सदस्य यहां बैठे रहें, उनको दिलचस्पी हो लेकिन उनको मौका न दिया जाये ।

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Member not to behave towards

the Chair in the same manner and in the same trend as he does towards the hon. Ministers here. I am sitting here as the Presiding Officer. I am not concerned whether there is any quorum or not. The hon. Member has no right to speak now. He did not send his name. I hope he will kindly spare me from that agony of taking any stern action. He should respect the Chair at least. I have called the hon. Minister.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH) : Mr. Chairman, Sir, I must admit that even though there is a temporary solution the long-term solution must be found out as otherwise this would not last for more than six months and we will face the same difficulty again. On this point I have no doubt whatsoever. I also agree with the question of employees in this trade. Very few people have spoken about them but it is also very important. A number of hon. Members who have spoken have said something about some employees, but there is a class known as 'extra' and the amount of difficulties that they are undergoing also has to be taken into consideration. It is true that I have not come forward before the House with a long-term solution, but there are certain difficulties. My first difficulty is that these theatres are in different States and I depend upon the States so far as exhibition is concerned. I must be able to persuade all the seventeen States. The problem in one State is not the same as the problem in another State. The problem which Bombay faces is quite different from the problem which Delhi faces or which the theatre owners in the mofussils face. Even the problems of theatre owners in the suburbs of Bombay are different from the problems of theatre-owners in Bombay itself (*Interruptions*). I understand my hon. friend's impatience. But I hope he will not want me to be impatient because if I do something in impatience that would be a wrong thing. Therefore, a thorough sweeping is absolutely necessary. On this point there is no doubt.

I am also trying to find out how the black money reaches the artistes, because it must originate somewhere. I am not prepared to make a definite statement, but it must end at the centre where the money is received. That means, at the exhibition centre some arrangement is made or at the producer's level he is debiting wrong expenses. How is he able to do it ? How is he able to pay blackmoney to the artistes? That must be found out. Unless you do this, the remedy will not be correct.

Now I will take up the points raised by various hon. Members. My hon. friend Shri Fernandes said that there is a lot of *gandaki*. It is there. But by saying *gandaki* the problem is not solved. It can be solved only by joint action by the Central Government and the State Governments.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : पहले आप तो शुरू करिये, फिर और लोग भी करेंगे ।

SHRI K. K. SHAH : You can use that word. But how do I start with the theatres ? Entertainment tax is in the province of the State Government. In the matter of production, the studies are located in the States.

So far as the employees of the studios are concerned, I may point out to my hon. friend what the Central Government have done. The matter is before a tripartite committee consisting of one representative each from the central organisations of employers and workers, the Ministry of Information and Broadcasting, the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation and the State Governments of Maharashtra, West Bengal, Madras and Andhra Pradesh. I have got a report from them indicating a number of difficulties. Who is to be included in the producer and who is to be included in the exhibitor and distributor ? Even in this definition they have taken such a long time. Who is an employee and who is the employer ? Because, a cinema star is working simultaneously at a number of places. An extra is working simultaneously at a number of places. Who will be the employer of that cinema star or that extra is also a moot point and has got to be decided. In the same way, who is the exhibitor ? A number of theatres have been leased out on a long-term basis. Now, those who have taken on a long-term basis, again, they have given it on weekly basis. Some give it on fixed rental basis and some

[Shri K. K. Shah]

give it on sharing basis. In the mofussil it is given on sharing basis and in the cities it is given on fixed rental basis. So far as the Central Government is concerned, a committee has already been appointed for the purpose of deciding the norms for films.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That Committee cannot go into these questions.

SHRI K. K. SHAH : Therefore, I have to enlarge the terms of reference of that committee.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप पूरे धंधे की जांच करने के लिये एक नयी कमेटी बनाइये।

SHRI K. K. SHAH : Now, all the maladies are known. It is not only a question of the remedy and the Patel Committee has gone into the details.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : वह बहुत पुरानी हो गई।

श्री के० के० शाह : पुरानी हो गई, ठीक बात है।

I must admit it has gone into it.

AN HON. MEMBER : There was no blackmoney at that time.

SHRI K. K. SHAH : I entirely accept the suggestion that—I would not say immediately—as soon as possible there should be a thorough examination.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप कमेटी बनाने का आश्वासन दीजिये। आप पूरे रास्ते हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं।

SHRI K. K. SHAH : How many committees shall we have ? Should we go on multiplying them ? I will consider this. I am not making any commitment. The committees also take a long time for taking evidence and so on.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What is needed is action. Let the Central Government initiate some action.

19.00 hrs.

SHRI K. K. SHAH : We have initiated action so far as putting up theatres is concerned. These theatres can only be put up by the State Governments.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about Delhi ? You can put up a theatre here. Let a beginning be made in New Delhi.

SHRI K. K. SHAH : For that, I have again to go to Finance. Theatres give a good return. It is correct they give a good return.

Let me tell my hon. friend that he should be happy to know that artistes have realised and a scheme is being formulated by them which will take concrete form in a week or two and they are going to submit that scheme which will, if that scheme goes through, eliminate black marketing so far as artistes are concerned.

I will tell you one of the suggestions. I do not say whether Finance will accept it or not. I do not want to make a commitment. There is a suggestion that if a percentage of the fees charged by artistes is ploughed back into a trust which will make it possible for them to get it back in 15 instalments after they have retired and then pay income-tax on what they get from that fund, they will have to disclose the maximum because, if they want to contribute to this fund a certain percentage of what they are receiving, unless they disclose the maximum, they will not be able to get back their share.

SHRI BABURAO PATEL : Most of them die before retirement.

SHRI K. K. SHAH : Then, it is also not correct to say that distributors and producers have no stake. On account of the minimum gaurantee, their stake is less. But the stake is there. The real malady is this. A film which used to cost Rs. 40 to 50 lakhs used to get back Rs. 60 lakhs. Since the cost has gone up and the saturation point has been reached, so far as the receipts are concerned, on account of the number of features being limited, they become flops. Really speaking, they are

not flops. If the cost would not have gone up, if the cost would have remained at Rs. 40 to 50 lakhs and if they would have recovered Rs. 60 lakhs as they used to recover in the past, they would not have become flops.

Here also, I cannot take any side. The complaint of the producers is that the exhibitors have raised the rental. That is also a complaint which does require investigation. It cannot be thrown out.

The suggestion made by Shri Himatsingka will, of course be taken into consideration. You don't expect me to act on that suggestion all of a sudden. But to say that the distribution should be taken over by the Central Government—I can only say that it can only be taken over by the State Government.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Even the State Government should not take over.

SHRI K. K. SHAH: So far as employees are concerned, that question is under consideration. My hon. friend can rest assured about that. I hope the Committee will complete its deliberations as soon as possible. But there also, there are a number of Acts that are in vogue today. I am not going to pass on the responsibility to somebody else. There is the Factories Act; there is the Payment of Wages Act; there is the Employees Provident Fund Act, the Shop Establishment Act, etc. All these Acts are there. There is the National Commission on Labour. (*Interruption*) This is a State subject.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur): Put a ceiling on the income of an actor when he is acting in one film.

SHRI K. K. SHAH: Even if you don't put a ceiling and if you only persuade or find out a way so that he discloses the entire income that he receives, that is more important.

Then, I come to the statement made by Mr. Baburao Patel. It is true producers have gone bankrupt. Distributors also have gone bankrupt. It is true that a few exhibitors have gone bankrupt.

SHRI BABURAO PATEL: Not one.

SHRI K. K. SHAH: That is possible. I am not prepared to contradict his statement. But that is because an exhibitor may not get a return. But an exhibitor cannot lose because he gets the rental. Therefore, the risk is on the distributor who gives the minimum guarantee.

SHRI GEORGE FERNANDES: Speculator.

SHRI BABURAO PATEL: Are you going to include it in the Monopolies Act?

SHRI K. K. SHAH: My hon. friend asks whether I am going to include it in the Monopolies Act. I want more theatres to come up. Any restriction is likely to curtail the number of theatres coming up. Today the cry is 'more theatres', 'more theatres'...

AN HON. MEMBER: You don't have cement for the theatres.

SHRI K.K. SHAH: That can be managed, if you can persuade people to put up theatres.

I accept Mr Vajpayee's suggestion that there should be a long-term solution.

Mr. Supakar was asking 'Why was this strike allowed to take place after settlement?'. Either I should have patience with them or if I have no patience, I must come forward with some action on the part of the Government. So far as action on the part of the Government is concerned, the studios are located in the States, the theatres are located in the States, the labour regulations are in the hands of the State: I am only passing the film.... (*Interruptions*) and financing. To what extent? I am not financing very much. But I will take this factor into consideration. Mr Supakar himself, however, agreed that they have come round and the production has started, the screening has started. In Madras also, screening of Hindi films has started. The question that is left is only in the North. It is not in the East or in the South or in the West. The only question is in the North. I hope, they will come round and in a day or two, short-term solution will be found. I am obliged to my hon. friends in this House. I would request them to make an all-sided effort, even with

[Shri K. K. Shah]

the States, so that a long-term solution can be found...

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): What about entertainment tax ?

SHRI K. K. SHAH : The entertainment tax also comes under the State. I will try my best. But do you want me to go round to all the 17 States and say, 'charge less' ? The best way would be, as was pointed out by my hon, friends, for the States to have more theatres, so that the entertainment tax can come down and still the recovery will be large enough.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till Monday.

19.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 29, 1968/ Vaisakha 9 1890 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.